एम० ई० एस० प्रधिकारियों द्वारा तकनीकी रूप से मंजूर इस परियोजना पर लागत 17,08,978 रुपये की आयेगी। यह धनराशि सरकार द्वारा फरवरी 1984 में पहले ही मंजूर कर दी गई है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रचार**

206. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के न तो अध्यक्ष हो और न प्रबन्ध निदेशक हो हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेते हैं जिससे इन बैंकों में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार में बाधा पड रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भाग 'क' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में तथा अधिसूचित कार्यालयों में जहां मूल काम मात्र हिन्दी में ही किया जाना चाहिये, हिन्दी में यह काम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):**

(क) चूंकि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं इसलिए वे समिति की बैठकों में भाग नही लेते। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के सदस्य है और उनकी अनुपस्थिति में बैंक के उप गवर्नर/कार्यपालक निदेशक बैठक में भाग लेते है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार इस समिति की सदस्य संख्या 30 तक ही सीमित है। बैंकों के अध्यक्षों को इस समिति का सदस्य बना दिए जाने से समिति का संचालन करना सहज नही रहैगा।

प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की क्षेत्र/मंडल/अंचल और प्रधान कार्यालय स्तरों पर अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां होती हैं जिनकी अध्यक्षता सम्बद्ध कार्यालयो के प्रमुख करते हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं जिनमें राजभाषा के प्रयोग के संबंध में समीक्षा की जाती है और काम मे सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों और 1983-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बैंकों से "क" क्षेत्र मे 66.7 प्रतिशत तक मूल पत्राचार हिन्दी में करने के लिए कहा गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन शाखाएं अधिसूचित करने के अलावा कुछ बैंकों ने अपनी कुछ ऐसी ग्रामीण शाखाओं का भी चयन किया है जहां सारा काम हिन्दी मे ही किया जाना है।

इस संबंध मे बैंकों के काम पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही रिपोर्टों के जरिए बराबर नजर रखी जाती है और जब कभी कोई त्रुटि दिखाई देती है तब संबंधित बैंक के अध्यक्ष को उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

**Vayudoot service in different places of Maharashtra**

207. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the progress so far made in starting the Vayudoot ser-

vices in different places of Maharashtra; and

(b) whether Government have decided upon any time limit to start Vayudoot services at remote places like Nanded and Akola of Maharashtra State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) Vayudoot is presently operating between Bombay and Kandla.

(b) No, Sir. Development of the essential infra-structure at Nanded is receiving active consideration.

**Export/Import of Sugar**

208. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India has been exporting sugar to other countries on bilateral basis;

(b) if so, the total quantity of sugar exported during 1983-84 and proposed to be exported during 1984-85 to different countries;

(c) whether Government have also been importing sugar; and

(d) if so, the total quantity of sugar imported during 1983-84 and proposed to be imported during 1984-85?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) The total quantity of sugar exported by Indian during 1983-84; was 8.13 lakh MTS. Out of this, 1.55 lakh MTS was on bilateral basis. In 1984-85, STC has contracted for export of 1.61 lakh MTS of sugar. Beyond this sugar exports have been held in abeyance.

(c) Yes, Sir.

(d) No imports of sugar were undertaken in 1983-84. Due to the sensitive nature of the international sugar market it would not be in our commercial interests to disclose any information regarding 1984-85.

**Trade deficit**

209. SHRI JAGADISH JANI:

SHRI J. P. GOYAL:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a record trade deficit of the country in the year 1983-84;

(b) if so, what are the figures of the trade deficit for the last three years;

(c) what are the reasons therefor;

(d) what measures have been taken by Government to augment the exports; and

(e) what measures are proposed to be taken to reduce the growing trade deficit during 1984-85?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (e) The figures of the trade deficit for the last three years are as follows:

(Rupees)

| Year | Trade Deficit |
|---|---|
| 1981-82 (Revised) | 5801·66 |
| 1982-83 (Revised) | 5525·78 |
| 1983-84* (Provisional) | 5951·16 |

*Provisional and subject to revision.

The higher trade deficit during 1983-84 is attributable mainly to two factors: (i) Port and dock workers strike which began on 16th March, 1984 (till 10th April, 1984) as a result of which no export consignments were handled at ports; and (ii) big increase in imports during the three-month period from December, 1983 to February, 1984.